



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

No. 174]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 10 अप्रैल, 2017

सं.टीएएमपी/7/2017-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, मुंबई पत्तन न्यास में नौचालन रत पोतों की मरम्मत करने के लिए ड्राई डॉक लाईसेंस(डीडीएल)/वैट डॉक अनुमति(डब्ल्यूपी) के लिए लाईसेंस नवीनीकरण/जारी करने हेतु मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/7/2017-एमबीपीटी

मुंबई पत्तन न्यास

.....

आवेदक

आदेश

(मार्च 2017 के 29वें दिन पारित)

(i) श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

यह मामला मुंबई पत्तन न्यास डॉक्स में आये पोतों की मरम्मत करने के लिए ड्राई डॉक लाईसेंस/ वैट डॉक अनुमति नवीनीकरण/जारी करने के लिए मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एमबीपीटी के 02 जनवरी, 2015 को पारित आदेश टीएएमपी/23/2013-एमबीपीटी में प्रचालित पोतों पर पोत का मरम्मत कार्य करने के लिए ड्राई डॉक अनुमति / लाइसेंस के नवीनीकरण/जारी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यद्यपि पतन ने नया वार्षिक ड्राई डॉक लाइसेंस/ नवीनीकरण के लिए रुपये 36,800/- की दर के समर्थन में परिकलन प्रस्तुत किया था, परंतु रुपये 1050/- प्रति आवेदन की दर के लिए कोई आधार नहीं बताया गया है और वार्षिक विशिष्ट कार्य श्रेणी-I के लिए रुपये 18,400/- की दर से तथा विशिष्ट कार्य श्रेणी-II के लिए 3700/- रुपये वार्षिक दर से पंजीकरण के समर्थन में कोई परिकलन नहीं दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि केवल रुपये 36,800/- की नये/नवीनीकृत वार्षिक ड्राई डॉक लाइसेंस जारी करने के अनुमोदन से एमबीपीटी का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ये सभी उसी प्रशुल्क श्रेणी का ही भाग है, इसलिए, कुल मिलाकर प्रस्तावित उपबंध अनुमोदित नहीं किया गया था। पतन को, इस संबंध में पृथक प्रस्ताव, जिसमें प्रशुल्क की सभी मदों की लागत विवरण दिया गया हो प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

3.1 एमबीपीटी के वर्तमान दरमानों में नौचालित पोतों पर विशिष्ट कार्य करने के लिए किसी लाइसेंस के नवीनीकरण/जारी करने तथा अनुमति के लिए कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, पतन ऐसे प्रभार, वर्ष 2005 से प्रभारित करता रहा है। वर्ष 2015 में इस प्राधिकरण के परामर्श/सुझाव पर एमबीपीटी ने, एमबीपीटी डॉक्स में नौचालित पोतों पर पोत मरम्मत का कार्य करने तथा बुकलेट की लागत के लिए ड्राई डॉक लाइसेंस/वैट डॉक अनुमति के नवीनीकरण/प्रदान करने के लिए लाइसेंस फीस के निर्धारण का प्रस्ताव प्रहस्तुत किया है।

3.2. एमबीपीटी द्वारा 12, जनवरी, 2017 के प्रस्ताव में किए गए उल्लेखों का सारांश इस प्रकार है।

- (i) पुस्तिका की आरंभिक लागत रु.500/- मझगांव डॉक लिमिटेड की वर्ष 2003-04 में पुस्तिका की लागत के आधार पर तय की गई थी। वैट लगने के कारण बाद में वर्ष 2006-07 में इसे बढ़ाकर रुपये 600/- तथा वर्ष 2009-10 में बढ़ाकर रुपये 1050/- कर दिया गया था। अन्तिम बार यह शुल्क 2006-07 में बढ़ाया गया था।
- (ii) ड्राई डॉक लाइसेंस / वैट डॉक अनुमति के लिए प्रशुल्क को 306 प्रतिशत बढ़ाने के लिए वह प्रस्ताव जो प्राधिकरण द्वारा पहले प्रस्तुत किया गया था वह प्रस्ताव वर्ष 2011-12 की प्रशासनिक रिपोर्ट में दर्शाए गए एक दिन के औसत पारिश्रमिक के आधार पर परिकलित किया गया था।
- (iii) तथापि, ड्राई डॉक लाइसेंस जारी/नवीकरण हेतु वैट डॉक अनुमति तथा अपेक्षित जन शक्ति के लिए सभी वास्तविक घटकों को गिना गया है, तथा वर्ष 2015-16 की प्रशासकीय रिपोर्ट में दर्शाए गए एक दिवसीय पारिश्रमिक के आधार पर जिसे वर्तमान प्रशुल्क की तुलना में 63.33 प्रतिशत बढ़ाया गया है नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- (iv) ड्राई लाइसेंस फीस/वैट डॉक अनुमति फीस तथा लाइसेंस/अनुमति के नवीनीकरण के परिकलन के आधार का विवरण नीचे दिया जाता है:-

प्रक्रिया/ड्यूटीरत कर्मचारियों का वर्ग और संख्या	मामले की जांच में प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा खपत किए गए कार्य दिवस	प्रत्येक मामले में व्यय कुल कार्य दिवस	दर/दिन (एमबीपीटी की प्रशा. निपोर्ट 2015-16 के आधार पर) (रु. लाख/दिन)	कुल रुपये
कार्यालय सहायक के लिए ऑफिस ब्वाय, क्लास.IV: सं. एक	प्रत्येक मामले में ¼ दिन	¼ दिन	सी1.VI. 5.62/365 =रु.1540/- प्रति दिन	385/-
फाईलें तैयार करने के लिए कार्यालय सहायक क्लास -III, एक	प्रत्येक मामले में 3 दिन	3 दिन	सी 1.III. 7.35/365 =	6042/-

			रु.2014/- प्रति दिन	
विवरण तैयार करने के लिए टंकक क्लास -III: एक	प्रत्येक मामले में एक दिन	1 दिन	सी 1.III. 7.35/365 = रु.2014/- प्रति दिन	लागू नहीं
निरीक्षण दौरे एवं सभी प्रलेखों जांच/सिफारिश के लिए (समितिके सदस्य) क्लास -1: तीन	प्रत्येक मामले में एक	3 दिन	सी 1.I. 11.43/365 = रु.3132/- प्रति दिन	9396/-
समीक्षा और अनुशंसा के लिए उप सीएमई: क्लास-I : एक	1/6 दिवस	1/6 दिवस	--उपर्युक्त --	522/-
समेकित नोट पर प्रशासनिक अनुमोदन के लिए सीएमई क्लास-I: एक	1/8 दिवस	1/6 दिवस	--उपर्युक्त --	392/-
स्थान की जांच के लिए समिति के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रत्येक मामले में रु.700/- की दर से प्रावधान	----	----	----	2100/-
लेखन सामग्री/कंप्यूटर संबंधी सामग्री/साइक्लोस्टाइलिंग आदि के लिए प्रत्येक मामले में रु.700/- की दर से प्रावधान .	----	----	----	700/-
			कुल	19537/-
			मान लो (शून्यांतक)	19600/-

लाइसेंस की वैधता 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो गई है तथा उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया जनवरी, 2017 से आरंभ की जानी है।

(v) उपर्युक्त उल्लेखों के आधार पर एमबीपीटी ने निम्नलिखित के लिए अनुमोदन की मांग की है:-

(क) ड्राई डॉक लाइसेंस/वैट डॉक अनुमति के लिए प्रशुल्क पर निम्नानुसार विचार किया जाए:-

ड्राई डॉक लाइसेंस फीस रु.19600/- (63.33% वृद्धि)	कार्य गतिविधि फीस	
	प्रति ड्राई डॉक कार्य गतिविधि	प्रति ड्राई डॉक कार्य गतिविधि
	रु.9800/- (लाइसेंस फीस का 50%)	रु.1960/- मान लो रु.2000/- (लाइसेंस फीस का 10%)

(ख) पुस्तिका की लागत रुपये 1000/- + वेट, अर्थात् यथावत रखने लिए, क्योंकि यह एमबीपीटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड की जाएगी।

3.3. तत्पश्चात, एमबीपीटी ने दिनांक 13 जनवरी, 2017 के अपने पत्र सं. एमईडी/एल/1-डी/5672 के अंतर्गत निम्नानुसार अनुरोध किया है:-

- 2016-17 में जारी की गई डीडीएल/डब्ल्यूडीपी की वैधता 31 मार्च, 2017 तक है। डीडीएल/डब्ल्यूडीपी जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया जनवरी, 2017 तक अवश्य शुरू की जानी है।
- वर्ष 2017-18 के लिए नयी दरें लागू करने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव किया गया है:

“वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लाईसेंस प्रशुल्क और कार्य गतिविधि प्रशुल्क दोनों, संशोधन हेतु प्राधिकरण के विचाराधीन हैं तथा वर्ष 2017-18 के लिए लागू होंगे। अनुमोदन के पश्चात यदि राशि का निर्धारण कम है तो एकत्र की गई राशि वापिस की जाएगी अथवा इसके विपरीत अधिक तय होने पर वसूल कर ली जाएगी।”

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार एमबीपीटी के दिनांक 12 जनवरी 2017 और 13 जनवरी, 2017 के पत्र की एक प्रति सभी संबंधित उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को परिचालित कर दी गई थी। किसी भी उपयोक्ता संगठन ने इस मामले पर निर्णय लिए जाने तक कोई टिपपणी नहीं भेजी है।

5.1. एमबीपीटी से हमारे 24 फरवरी, 2017 के पत्र के माध्यम से कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया गया था कि एमबीपीटी ने दिनांक 03 फरवरी, 2017 के पत्र के माध्यम से प्रत्युत्तर भेजा है। प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी तथा उस पर एमबीपीटी के उत्तर नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं :

क्र.सं.	अपेक्षित सूचना / स्पष्टीकरण	एम बी पी टी का उत्तर
(i)	एमबीपीटी, प्राधिकरण द्वारा उन उपयोक्ताओं/ उपयोक्ता संगठनों जिनके साथ परामर्श किया जा चुका है, के अलावा अन्य उपयोक्ताओं/ उपयोक्ता संगठनों की जानकारी दे जिनसे इस मामले में परामर्श किया जा सकता है।	पोत मरम्मत कार्य करने वाली फर्मों/ ठेकेदारों, पोतों के मालिकों / एजेंटों को, मरम्मत कार्य की सेवाएं प्रदान करने के लिए; जिन्हें अपने पोतों की मरम्मत सर्वेक्षण हेतु एमबीपीटी ड्राई / वैट डैक आबंटित किया गया है और जो एमबीपीटी के पास वर्ष 2016-17 के लिए मरम्मत कार्य हेतु अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं की एक सूची प्रस्तुत की गई है। (एमबीपीटी ने, वर्ष 2016-17 के दौरान, उन 89 फर्मों का सम्पर्क विवरण प्रस्तुत किया है जिन्हें ड्राई डॉक लाईसेंस जारी किया गया है।
(ii)	एमबीपीटी ने 13 जनवरी, 2017 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित दरों को तदर्थ आधार पर लागू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है ताकि वह इस दर को वर्ष 2017-18 के दौरान लागू कर सके। इस संबंध में प्रशुल्क नीति के खंड 5.7.4 के उल्लेखानुसार लागू किया जाने वाला प्रशुल्क संबंधित उपयोक्ताओं से परामर्श करके तय किया जाना चाहिए। एमबीपीटी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे परामर्शी प्रक्रिया सम्पन्न होने का प्रमाण मिलता हो।	ड्राई डॉक लाईसेंस/अनुमति के लिए संशोधित दरों पर विचार करने के लिए वर्तमान में पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों के साथ 07.02.2017 को एक बैठक का आयोजन किया गया है।
(iii)	एमबीपीटी के दरमानों में, प्रस्तावित लेवी को अधिशासित करने वाली शर्तें तथा दरमानों के प्रारूप, शामिल करने के लिए प्रस्तुत करें।	दरमानों के प्ररूप प्रस्ताव के साथ पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा यही प्रभार, पाददर्शिता और उपयोक्ताओं / प्रत्याशी लाईसेंस धारकों की जानकारी के लिए एमबीपीटी के दरमानों में शामिल किए जाने हैं।
(iv)	प्रस्तावित दरमानों में एक विसंगति दिखायी देती है क्योंकि प्रति ड्राई डॉक क्रियान्वयन के लिए प्रशुल्क प्रस्तावित दर 9800/- रुपये तथा रुपये 2000/- भी दर्शायी गई है। कृपया स्थिति को स्पष्ट करें।	‘क’ और ‘ख’ दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ‘क’ श्रेणी के कार्य ड्राई डॉक कार्य कहलाते हैं जो केवल डॉक में ही पूरे किए जाते हैं जैसे कि पोत के पानी में रहने वाले भाग की मरम्मत। ये कार्य बड़े कार्य होते हैं। मात्रा और विलंब व कार्य की किस्म की दृष्टि से ऐसे कार्य जो अधिक बड़े होते हैं के लिए, फर्मों/ठेकेदार लगाए जाते हैं। इससे पूर्व ऐसे कार्यों के लिए प्रशुल्क 6000/- रुपये था जिसके स्थान पर अब 9800/- रुपये का प्रस्ताव किया गया है। ‘ख’ श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्य वैट डॉक कार्य कहे जाते हैं। ऐसे कार्य तैरते हुए पोत पर किए जा सकते हैं, ऐसे कार्यों के लिए पूर्ववर्ती प्रशुल्क रुपये 1200/- था जिसके स्थान पर अब रुपये 2000/- का प्रस्ताव किया गया है।

(v)	<p>एमबीपीटी से अनुरोध है कि सत्यापन दौरे के लिए, 3 सदस्यों हेतु रुपये 700/- की दर से प्रशुल्क तथा प्रत्येक मामले के लिए रुपये 700/- की लेखन सामग्री हेतु प्रशुल्क का आधार बताएं।</p>	<p>तीन सदस्यीय समिति पंजीकृत फर्म/ ठेकेदार के कार्यालय/कार्यशाला/गोदाम मशीनरी तथा स्थान का तकनीकी निरीक्षण करने के लिए तथा फर्मों द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों की जांच करने के लिए है। वर्ष 2005 से इसमें वृद्धि नहीं की गई है।</p> <p>जहां तक लेखन सामग्री का प्रश्न है, उल्लेख किया जाता है कि लाइसेंस/अनुमति के नवीनीकरण के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है तथा एमबीपीटी की वेबसाइट पर भी लोड किया जाता है।</p> <p>वर्तमान में पंजीकृत फर्मों को इस आशय का एक सूचना पत्र भी प्रेषित किया गया था कि यदि वे इच्छुक हों तो वे अपना लाइसेंस/ अनुमति पत्र का नवीनीकरण करवा सकते हैं। सभी दस्तावेज उपयुक्त पाए जाने के पश्चात फर्मों को लाइसेंस / अनुमति प्रदान कर दी जाती है। इससे संबंधित प्रशुल्क में वृद्धि नहीं की गई है।</p>
-----	--	---

5.2 एमबीपीटी द्वारा प्रदत्त 89 फर्मों की सूची के अनुसार सभी फर्मों से परामर्श करना बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी इसलिए एम बी पी टी से 13 फरवरी, 2017 के पत्र द्वारा यह जांचने का अनुरोध किया गया कि क्या ये फर्म किसी संस्था का भाग तो नहीं हैं और उस संस्था का संपर्क पता बताएं उस संस्था से परामर्श किया जा सके। एमबीपीटी से यह अनुरोध भी किया गया कि यदि वे किसी उपयोक्ता संगठन का भाग नहीं हैं तो वे किसी भी सुविधा के प्रमुख उपयोक्ताओं का संपर्क विवरण प्रस्तुत करें।

5.3 इसके अतिरिक्त, क्योंकि एमबीपीटी ने मौजूदा पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों के साथ ड्राई डॉक लाइसेंस/अनुमति हेतु संशोधित दरों पर विचार करने के लिए बैठक के आयोजन का संकेत दिया था। एमबीपीटी को हमारे 13 फरवरी, 2017 के पत्र के द्वारा प्रतिभागियों की सूची तथा कथित बैठक की कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

5.4 एमबीपीटी ने दिनांक 13 फरवरी, 2017 तथा 16 फरवरी, 2017 के अपने पत्रों में प्रत्युत्तर रूप में निम्न उल्लेख किए हैं;

- (i) हमारे रिकार्ड के अनुसार; ड्राई डॉक लाइसेंस/वैट डॉट अनुमति धारकों की कोई संस्था/संगठन नहीं है।
- (ii) एमबीपीटी ने दिनांक 07 फरवरी, 2017 को, संशोधित दरों पर विचार करने के लिए पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों के साथ एक बैठक आयोजित की थी। 147 फर्मों/ ठेकेदारों में से केवल 57 ने बैठक में भाग लिया। फर्मों/ठेकेदारों को इस संबंध में अपनी-अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया। इनमें से केवल 9 फर्मों ने अपनी फीडबैक भेजी है। इनमें से 8 फर्मों ने अपनी सहमति दी है और एक फर्म प्रस्तावित संशोधित दर से असहमत है।
(एम बी पी टी ने 07.02.2017 को आयोजित बैठक में उपस्थित फर्मों की सूची की प्रति संलग्न की है तथा फीड बैक देने वाली 9 फर्मों के ई-मेल की प्रति भी प्रस्तुत कर दी है।)

5.5. प्राधिकरण के अनुरोध के अनुरूप यद्यपि एमबीपीटी ने पुष्टि की है कि ड्राई डॉक लाइसेंस / वैट डॉक अनुमति धारकों की कोई संगठन/ संस्था नहीं है, एमबीपीटी ने यथा अपेक्षित प्रमुख सुविधा उपयोक्ताओं के संपर्क विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार प्राधिकरण ने 07 मार्च, 2017 के पत्र के द्वारा एमबीपीटी से पुनः अनुरोध किया कि वह सुविधा के प्रमुख उपयोक्ताओं के संपर्क विवरण प्रस्तुत करें। एमबीपीटी ने इस मामले पर अंतिम कार्यवाही करने तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

6. संदर्भित मामले में 14 मार्च, 2017 को एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों तथा एमबीपीटी ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की।

7. इस मामले पर परामर्शी प्रक्रिया से संबंधित कार्यवाही प्राधिकरण कार्यालय के रिकार्ड में दर्ज है। संबंधित पक्षों के पृथक-पृथक तर्कों का विवरण संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

8. मामले पर समग्र सोच विचार और एकत्रित जानकारी के आधार पर निम्न स्थिति उजागर होती है:-

- (i) मुंबई पतन न्यास के वर्तमान दरमानों में नौचालित पोतों पर विशिष्ट मरम्मत कार्य करने के लिए डाई डॉक अनुमति के नवीनीकरण / जारी करने के लिए कोई लाइसेंस प्रशुल्क निर्धारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में एमबीपीटी ने जनवरी, 2017 में नौचालित पोतों पर मरम्मत के लिए डाई डॉक लाइसेंस जारी करने / नवीनीकरण के लिए / वैट डॉक अनुमति के लिए एमबीपीटी डॉक्स में, लाइसेंस प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एमबीपीटी द्वारा लाइसेंस जारी करने का आशय, पोत परिसर में डाई डॉक या वैट डॉक पर कार्य के लिए एक पक्ष (फर्म) को प्राधिकृत करना है और यह कि कोई अनाधिकृत पक्ष पतन के परिसर में प्रविष्ट न कर सके। पतन ने यह भी उल्लेख किया है कि इससे फर्मों (पक्षों) के दिन-प्रति के कार्यों में कोई खलल नहीं पड़ेगा।
- (ii) यद्यपि डाई डॉक / पोत मरम्मत हेतु अनुमति के लिए एम बी पी टी के द्वारा लाइसेंस हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, पतन के उल्लेख से पता चलता है कि पतन वर्ष 2005 से कुछ लाइसेंस फीस लेता रहा है। पतन किस प्राधिकार के तहत यह प्रभार वसूल कर रहा था, ज्ञात नहीं है। एमबीपीटी से अनुरोध किया जाता है कि वह प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना इस प्रकार के किसी प्रभार को वसूल न करे। फिर भी 01 अप्रैल, 2017 से आगामी अवधि के लिए लाइसेंस प्रशुल्क लगाने का यह प्रस्ताव निपटान हेतु स्वीकार किया जाता है।
- (iii) एमबीपीटी ने डाई डॉक लाइसेंस फीस रुपये 19600/- तथा डाई डॉक कार्य प्रशुल्क रुपये 9800/- तथा प्रति वैट डॉक कार्य प्रशुल्क रुपये 2000/- का प्रस्ताव किया है। पतन ने पुस्तिका के लिए भी रुपये 1000/- प्रति पुस्तक वैट का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित दरों के संबंध में लागत घटक पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।
- (iv) एमबीपीटी के द्वारा पतन के विवरण में दर्शायी गयी विभिन्न श्रमशक्ति वर्ग और प्रत्येक द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया में लगने वाले समय तथा लेखन सामग्री की लागत जो आदेश के प्रथम भाग में दी गई है को ध्यान में रखते हुए वार्षिक लाइसेंस फीस रुपये 19600/- का प्रस्ताव किया गया है। विभिन्न प्रकार की कार्मिकों की संख्या का भाग पतन के निर्णय पर आधारित होती है और यह प्राधिकरण पतन द्वारा प्रस्तावित कार्मिकों की मांग की गहराई में अधिक जानकारी लेने का इच्छुक नहीं है प्रत्येक प्रकार की कार्मिकों की लागत वर्ष 2015-16 की लागत के आधार पर है अतः विश्वस्नीय है।
लेखन सामग्री की लागत में लाइसेंस/अनुमति के नवीनीकरण के आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन, कंप्यूटर संबंधी लेखन सामग्री, साइक्लोस्टाइलिंग का उल्लेख है। इस संबंध में पतन द्वारा किया गया आकलन विश्वस्नीय है।
एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत परिकलन के आधार पर डाई डॉक लाइसेंस फीस की प्रस्तावित वार्षिक दर का अनुमोदन किया जाता है।

- (v) प्रति ड्राई डॉक कार्य के लिए प्रशुल्क वार्षिक ड्राई डॉक लाइसेंस फीस अर्थात् रुपये 19600/- का 50 प्रतिशत का प्रस्ताव किया गया है। प्रति वैट डॉक कार्य के पतन ने वार्षिक ड्राई डॉक लाइसेंस फीस अर्थात् 19600/- रुपये का लगभग 10 प्रतिशत अर्थात् 2000/- रुपये का शून्यांक प्रस्ताव किया है। यद्यपि पतन ने ड्राई डॉक और वैट डॉक कार्यों के लिए वार्षिक ड्राई डॉक लाइसेंस फीस का क्रमशः 50 प्रतिशत और 10 प्रतिशत निर्धारण करने के कारण उल्लेख नहीं किया है फिर भी देखने में आया है कि मौजूदा कार्य प्रशुल्क के लिए भी यही तरीका अपनाया गया है। अन्य शब्दों में वर्तमान प्रति ड्राई डॉक और वैट डॉक कार्यों के लिए भी वार्षिक ड्राई डॉक लाइसेंस फीस का क्रमशः 50 प्रतिशत (रुपये 6000/-) और 10 प्रतिशत (रुपये 1200/-) निर्धारित किया हुआ है। ऐसी स्थिति तथा इस बात पर विचार करते हुए कि पतन द्वारा प्रस्तावित दरों पर उपयोक्ताओं / उपयोक्ता संगठनों ने आपत्ति दर्ज नहीं की है, ड्राई प्रति डॉक कार्य के लिए 9800/- रुपये और प्रति वैट डॉक कार्य के लिए रुपये 2000/- का एमबीपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।
- (vi) सूचित किया गया है कि पुस्तिका की लागत रुपये 1000/- +वैट 2006-07 से प्रचालित है। यही दर 01 अप्रैल, 2017 से चालू रखने की अनुमति दी जाती है क्योंकि उपयोक्ताओं / उपयोक्ता संगठनों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की है।
- (vii) यह मानते हुए कि एमबीपीटी ने प्रस्तावित दरों के 01.04.2017 से प्रभावी होने का प्रस्ताव किया है और किसी भी उपयोक्ता उपयोक्ता संगठन ने इन्हें 01.04.2017 से प्रभावी करने पर आपत्ति दर्ज नहीं की है, यह प्राधिकरण इन दरों को 01.04.2017 से लागू करने का अनुमोदन करता है।
- (viii) प्राधिकरण द्वारा इन प्रभारों के लिए अनुमोदन पर कुछ वित्तीय निहितार्थ भी है क्योंकि एमबीपीटी द्वारा ये प्रभार लेने पर अतिरिक्त राजस्व अर्जित होगा। एमबीपीटी ने इस कारण से प्रति वर्ष लगभग 30 लाख रुपये के उपार्जन की संभावना व्यक्त की है। क्योंकि एमबीपीटी प्रस्तावित दरों से आकलित अतिरिक्त आय का वर्ष 2016 में, एमबीपीटी के प्रस्ताव के सामान्य संशोधन के बारे में निर्णय लेते समय, अनुमान नहीं लगाया गया था, इसलिए राजस्व को यथावत रखने के लिए किसी अन्य दर में समंजन पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि तटस्थ राजस्व की स्थिति का प्रश्न तभी उठता है जब पतन को वह प्रशुल्क पहले ही अदा किया गया हो और नये प्रशुल्क के तौर पर पुनः दिया जाना हो। एमबीपीटी के इस मामले में समरण: रहे कि जून, 2016 में निर्णीत एमबीपीटी के दरमानों में सामान्य संशोधन से संबंधित आदेश में रुपये 1572.19 करोड़ के सूचकांकित वार्षिक राजस्व मांग के स्थान पर एमबीपीटी द्वारा परिकलित मांग केवल रुपये 1300.64 करोड़ थी। जिससे राजस्व में 265.55 करोड़ रुपये का अंतर रह गया था। अतः प्रस्तावित प्रभारों से अनोपार्जित आय 30 लाख रुपये के लगाने पर भी यह अंतर बना रहेगा। इसलिए अन्य दरों में समंजन का यह प्रश्न अनुरक्षित राजस्व को तटस्थ बनाए रखने के लिए नहीं बनता है।

9.1. उपर्युक्त दिए गए कारणों और समग्र सोच-विचार के पश्चात यह प्राधिकरण एमबीपीटी के वर्तमान दरमानों में खंड 9.6 में निम्नलिखित प्रावधान शामिल करने का अनुमोदन करता है:

(क) ड्राई डॉक लाइसेंस/ वैट डॉक अनुमति जारी करने के लिए प्रशुल्क:

वार्षिक ड्राई डॉक लाइसेंस फीस रु.19600/-	कार्य गतिविधि फीस	
	प्रति ड्राई डॉक कार्य गतिविधि	प्रति वैट डॉक कार्य गतिविधि
	रु. 9800/-	रु. 2000/-

(ख) पुस्तिका की लागत अर्थात् रुपये 1000 + वैट

9.2. अब अनुमोदित उपर्युक्त दरें 01.04.2017 से लागू रहेंगी और एमबीपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता के साथ-साथ 31 मार्च, 2019 तक लागू रहेंगी। यह अनुमोदन इसके पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा इस में विस्तार न किया जाए।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./34/17]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, 10th April, 2017

No. TAMP/7/2017-MBPT.— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for renewal/ issue of dry dock license (DDL)/ Wet Dock Permission (WDP) to carry out Ship repairs on board vessels in Mumbai Port Trust Docks, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/7/2017-MBPT

The Mumbai Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of March, 2017)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for renewal/ issue of dry dock license (DDL)/ Wet Dock Permission (WDP) to carry out Ship repairs on board vessels in Mumbai Port Trust Docks.

2. The MBPT in the proceedings relating to its General revision of its Scale of Rates which culminated into tariff Order No.TAMP/23/2013-MBPT dated 2 January 2015 had proposed licence fees for renewal / issue of dry dock permission for carrying out ship repair job on board vessels. Though the port had furnished workings in support of the rate of ₹ 36800/- for issue of new/ renewal of Annual Dry Dock Licence, no basis had been furnished to arrive at the rate of ₹ 1050/- per application form and no workings had been furnished to arrive at the rate of ₹18400/- for issue of Annual Specialised Job Category I registration and ₹ 3700/- per job per year for issue of Annual Specialised Job category II. In the absence of requisite details and workings the proposed charges for application form, job category I and II were not approved. Further, since approval to the rate of ₹36,800/- for issue of new / renewal of Annual Dry Dock licence alone, may not serve any purpose to MBPT, as they all form part of same tariff category, the proposed provision in totality was not approved. The port was advised to file a separate proposal in this regard, supported by cost details for all tariff items.

3.1. The existing Scale of Rates of MBPT do not prescribe any Licence fees for renewal/ issue of dry dock/ permission for carrying out ship repair specialized job on board vessels. The port has, however, been levying these charges since 2005. Based on the advice of this Authority in 2015, the MBPT has now come up with a proposal for fixation of Licence Fees for renewal / issue of dry dock license (DDL) / Wet Dock Permission (WDP) to carry out Ship repairs on board vessels in MBPT Docks and cost of Booklet.

3.2. The submissions made by MBPT proposal dated 12 January, 2017 are summarised below:

- (i). The initial cost of the booklet of ₹500/- was fixed on the basis of cost of booklet of Mazgaon Dock Ltd. in the year 2003-04. Later it was increased to ₹600/- in the year 2006-07 and ₹1000/- in 2009-10 and the cost of booklet was fixed to ₹1050/- on the introduction VAT. The fee was last revised in 2006-07.

- (ii) The proposal, which was forwarded to TAMP earlier to increase the fees of Dry Dock Licence / Wet Dock Permission by 306% was calculated on the average one day wages shown in the Administrative Report 2011-12.
- (iii) However, taking into account all the realistic facts for issue/ renew the Dry Dock License/ Wet Dock Permission, and the manpower requirement, a new proposal is prepared, based on the average one day wages shown in the Administrative Report, 2015-16, which is increased by 63.33% from the existing fees.
- (iv) The statement showing the base of calculation of Dry license fee/ wet dock permission fee and levy on renewal of license/ permission is shown below:

Class & No. of employees involved in the processing and duties	No of days per employee consumed in checking the case	Total No. of working days consumed for each case	Rate/ Day (based on 2015-16 MBPT Adm. Report) (₹ in lakh/day)	Total in Rupees
CI.IV-1 No. (office boy-for office assistance)	¼ day for each case	¼ day	C1.VI. 5.62/365 = ₹1540/- per day	385/-
CI.III-1 No. (office Asstt.-for compiling the files)	3 days for each case	3 days	C1.III. 7.35/365 = ₹2014/- per day	6042/-
CI.III-1 No. (Typist for preparation of statements)	1 day for each case	1 day	C1.III. 7.35/365 = ₹2014/- per day	N.A.
CI.I-3 Nos. officers. (Committee members for verification visits and checking all documents / recommending)	1 day for each case	3 days	C1.I. 11.43/365 = ₹3132/- per day	9396/-
CI.I-1 No. (Dy. CME-for reviewing and recommending)	One sixth day	One sixth day	-- do --	522/-
CI.I-1 No. (CME - for Admin approval on consolidated note)	One eight day	One eight day	-- do --	392/-
Provision for verification site visits @₹700/- for each committee member for each case)	----	----	----	2100/-
Provision for Stationery /computer related stationery / cyclostyling etc. @ ₹700 for each case.	----	----	----	700/-
			Total	19537/-
			Say	19600/-

The validity of license fees has expired on 31 March 2016 and process for the renewal licence has to be started in the month of January, 2017.

- (v). Based on the above submissions, the MBPT has sought the approval for the following:
- (a) To consider the fees for issue of Dry Dock license / wet dock permission as given below:

Proposed Dry Dock License Fees / Activity fees

Dry Dock License Fees ₹19600/- (increased by 63.33%)	Activity Fees	
	Per Dry Dock Activity	Per Dry Dock Activity
	₹9800/- (50% of License Fees)	₹1960/- say ₹2000/- (10% of License Fees)

- (b) To keep the same cost of Booklet i.e. of ₹1000/- + VAT, being the booklet will be directly downloaded by the firms / contractor from MBPT website.

3.3. Subsequently, the MBPT vide its letter No. MEED/L/1-D/5672 dated 13 January, 2017 has made the following submissions:

- (i) The validity of the DDL/ WDP, issued in 2016-17 is upto 31 March, 2017. The process for inviting application to issue/ renew the DDL/ WDP has to be initiated in the month of January 2017.

- (ii) It is proposed to apply the proposed new rates for the year 2017-18 and intimate to the firms as under:

“Annual Licence fee and Activity fee for the year 2016-17 are under revision and consideration by TAMP and will be levied for the year 2017-18. On approval, if the amount is less, then collected excess amount will be refunded and vice – versa.”

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy each of the MBPT letters dated 12 January 2017 and 13 January 2017 was circulated to all the concerned users/ user organisations seeking their comments. None of the users / user organisations have furnished any comments till the case was finalised.

5.1. The MBPT was requested vide our letter dated 24 January 2017 to furnish some clarification. The MBPT has responded vide its letter dated 03 February 2017. The information sought by us and the response of MBPT thereon are tabulated below:

No.	Information/ clarification sought by us	Response of MBPT
(i).	The MBPT to indicate any other major users/ user organisations who may be consulted in this case, in addition to the users/ user organisations consulted by TAMP.	The list of firms / contractors, who are in ship repair activity and wish to provide their repair service to the owner / agent of the vessel, who have been allotted MBPT dry / wet docks for survey / repair of their vessels and who may register their firm with MBPT as a ship repairer in the year 2016-17 is furnished. (The MBPT has given the contact details in respect of 89 firms who have been issued dry dock licence in the year 2016-17.)
(ii).	The MBPT vide its letter dated 13 January 2017 has sought approval for levy of the proposed rates on adhoc basis, so as to enable it apply the proposed new rates for the year 2017-18. In this regard, as stipulated in Clause 5.7.4 of the Tariff Policy, 2015, the adhoc rate to be operated must be in consultation with the concerned user(s). The MBPT has not furnished any document which reflects the consultation process undertaken by it.	A meeting has been arranged on 07.02.2017 with the existing registered firms / contractor to discuss on the revised rate of dry dock license/ permission.
(iii).	The MBPT to furnish the draft Scale of Rates and the conditionalities governing the proposed levy, for incorporation in the MBPT Scale of Rates.	The draft Scale of Rates has already been furnished with the proposal and the same charges has to be incorporated in the MBPT Scale of Rates for transparency and for information of the users / prospective licensee.
(iv)	There appears to be an anomaly in the proposed rates as the activity fees per dry dock activity is seen to have been prescribed at ₹9800/- and also ₹2000/-. Please clarify this position.	There are two type of jobs (A&B). The jobs come under 'A' category are called dry dock activity, which are carried out only in dry dock such as repairs to underwater portion of the vessel. These jobs are major work. The firms / contractors engage to carry out these jobs which are larger in nature by quantity as well as finance. The previous fee for the same was ₹6000/- which is now proposed as ₹9800/-. The jobs come under 'B' category is called wet dock activity. Such type of jobs can be carried out in floating condition. The previous fee for the same was ₹1200/- which is now proposed as ₹2000/-
(v)	The MBPT is requested to furnish the basis for fee for verification site visits of 3 members @ ₹700/- per member and ₹700/- towards stationery for each case.	The Technical Inspection Committee of 03 members visit the site (office / workshop / godown) of the firms / contractors to verify the information given by the firms for registration i.e. office premises / workshop / machineries and verify the documents furnished by the firms. The same has not been increased since 2005.

		<p>Regarding the stationery charges it is stated than an advertise, to invite the application for issue / renewal of licence / permission is published in the newspapers and as well as post on MBPT website.</p> <p>An intimation letter was also issued to the existing register firms to renew their licence / permission if they desire to do so. After verifying all documents, the firms are issued licence / permission, if found suitable. The fee of the same has not been increased.</p>
--	--	--

5.2. Given that it may be very extensive exercise to consult all the 89 firms as per the list furnished by MBPT, the MBPT was requested vide our letter dated 13 February 2017 to examine whether these firms form part of any association, and furnish the contact details of the said association so as to enable us consult the said association. The MBPT was also requested to furnish the contact details of major users of the facility, if they are not part of any user associations.

5.3. Further, since the MBPT had indicated about having arranged a meeting with the existing registered firms / contractor to discuss on the revised rate of dry dock license/ permission, the MBPT was requested vide our above referred letter dated 13 February 2017 to furnish the list of participants and the Minutes of the said meeting.

5.4. The MBPT has responded vide its letters dated 13 February 2017 and 16 February 2017. The MBPT has stated the following:

- (i) There is no association of the Dry Dock License/ Wet Dock Permission holders as per our records.
- (ii) The MBPT had fixed a meeting with existing registered firms/ contractors on 07 February 2017 to discuss on the revised rate. Out of 147 Nos. firms/ contractors, only 57 Nos. attended the meeting. The firms/ contractors were requested to send their comments/ concurrence. Only Nine firms have sent their feedback. Out of these, only 08 firms have given concurrence and the remaining 1 firm has not concurred with the proposed revision of licence fee.

(The MBPT has furnished a copy of the Attendance list reflecting the firms who attended the meeting held on 07.02.2017 and has also furnished the copies of the e-mails of 9 parties who have given their feedback.)

5.5. As requested by us, though the MBPT has confirmed that there is no association of the Dry Dock License/ Wet Dock Permission holders, the MBPT has not furnished the contact details of major users of the facility, as sought by us. Thus, we have vide our letter dated 07 March 2017 once again requested MBPT to furnish the contact details of major users of the facility. The MBPT has not responded till finalization of this case.

6. A joint hearing on the case in reference was held on 14 March 2017 at the Office of this Authority. At the joint hearing, the users/ user organisations and the MBPT have made their submissions:

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>

8. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following points emerges:

- (i) The existing Scale of Rates of Mumbai Port Trust (MBPT) does not prescribe any Licence fees for renewal/ issue of dry dock/ permission for carrying out ship repair specialized job on board vessels. In view of this position, the MBPT has come up with a proposal in January 2017 for fixation of Licence Fees for renewal/ issue of dry dock license (DDL)/ Wet Dock Permission (WDP) to carry out Ship repairs on board vessels in MBPT Docks. The intention of issue of licence by MBPT is reported to authorize a party to undertake dry docking or wet docking at the port premises and that any unsolicited party does not enter the port premises. The Port has also stated that it does not interfere in the day to day activities carried out by the parties.
- (ii) Though the existing Scale of Rates of MBPT does not have a specific provision for levy of Licence fees for renewal/ issue of dry dock/ permission for carrying out ship repair, it is inferred from the

submissions made by the Port that the Port has been levying some Licence fees in this regard since 2005. The authority under which the Port has been levying these charges without the approval of this Authority is not known. The MBPT is advised to refrain from levying any charges without the specific approval of this Authority. Nevertheless, given that the proposal of the Port is for prescription of the Licence fees for a future period with effect from 01 April 2017, the proposal is taken up for disposal.

- (iii) The MBPT has proposed the annual Dry Dock License Fees at ₹19600/-, the activity Fees for per Dry Dock Activity at ₹9800/- and activity fees for per Wet Dock Activity at ₹2000/-. The Port has also proposed the cost of Booklet at ₹1000/- + VAT. The cost components in respect of the proposed rates are discussed in the succeeding paragraphs.
- (iv) The annual licence fees of ₹19600/- has been proposed by the MBPT by taking into account the cost involved in deployment of various category of manpower and the time that will be devoted by each manpower to process a licence, as given in detail by the port as well as the cost of stationery, which has been brought out in the earlier part of the Order.

The requirement of number of various type of manpower is the judgment of the Port and this Authority does not like to delve deep in the manpower requirement as proposed by the Port. The cost of each type of manpower is reported to be based on the actuals for the year 2015-16 and hence, is relied upon.

The stationery cost is reported to include the cost towards publishing of advertisement inviting the application for issue/ renewal of licence/ permission in the newspapers, computer related stationery, cyclostyling. The judgment of the port with regard to estimation of cost in this regard is relied upon.

Based on the working furnished by the MBPT, the rate of ₹19600/- towards annual Dry Dock License Fees as proposed by the Port is approved.

- (v) The activity Fees for per Dry Dock Activity at ₹9800/- has been proposed by the Port at 50% of the annual Dry Dock License Fees of ₹19600/-. The activity Fees for per Wet Dock Activity at ₹ 2000/- has been proposed by the Port at about 10% of the annual Dry Dock License Fees at ₹19600/- and rounded off to ₹2000/-. Though the Port has not explained the reason for prescribing activity Fees for per Dry Dock and Wet dock Activity at 50% and 10% of the annual Dry Dock License Fees respectively, it is seen that the existing activity fees being levied by the MBPT also follow the same pattern. In other words, the existing activity Fees for per Dry Dock and Wet dock Activity have been prescribed at 50% (₹6000/-) and 10% (₹1200/-) of the annual Dry Dock License Fees (₹12000/-) respectively. In view of this position and considering that the users/ user organisations present in the joint hearing have not objected to the rates proposed by the Port, the activity Fees for per Dry Dock Activity at ₹9800/- and the activity Fees for per Wet Dock Activity at ₹2000/- as proposed by the MBPT are approved.
- (vi) The cost for the booklet at ₹1000/- plus VAT is reported to be the rate prevailing since 2006-07. The same is allowed to continue with effect from 01 April 2017, given that the users/ user organisations have not objected to the rate proposed by MBPT.
- (vii) Considering that the MBPT has proposed for the rates to come into effect from 01 April 2017 and given that none of the users/ user organisations have objected to the levy of the rates approved now with effect from 01 April 2017, this Authority is inclined to approve levy of the rates approved now with effect from 01 April 2017.
- (viii) The approval accorded by this Authority for the levy of charges would involve some financial implication, as MBPT may earn additional revenue on account of levy of the charges. The MBPT has quantified the income to be earned by it on account of the proposed levy to be around ₹30 lakhs per annum. Since the said additional income estimated to be earned by MBPT from the proposed rate had not been anticipated and factored while deciding the general revision proposal of MBPT disposed in 2016, there may be a view that some other rate should be adjusted to maintain revenue neutral position.

In this regard, it is relevant here to mention that the question of ensuring a revenue neutral position arises when a port has already been given tariff whatever is due to it, based on the estimated cost position and thereafter it is to be again granted a new tariff. However, in the case of MBPT, it is relevant to recall that in the Order relating to the MBPT general revision case disposed in June 2016, as against the Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) of ₹1572.19 crores, the Revenue Estimation at the proposed level of tariff as worked out by MBPT was only ₹1306.64 crores, thereby

leaving a revenue gap of ₹265.55 crores left uncovered by the Port. So even with the income to the tune of ₹30 lakhs from the levy of the proposed charges, the gap will continue to remain. Therefore, the question of adjustment in some other rate to maintain revenue neutral position does not arise.

9.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves insertion of the following provision as Section 9.6 in the existing Scale of Rates of MBPT:

- (a). Fees for issue of Dry Dock license / wet dock permission

Annual Dry Dock License Fees ₹19600/-	Activity Fees	
	Per Dry Dock Activity	Per Wet Dock Activity
	₹9800/-	₹2000/-

- (b). Cost of Booklet i.e. of ₹1000/- + VAT.

9.2. The levy of the above rates approved now will be effective from 01 April, 2017 and may remain co-terminus with the validity of the existing Scale of Rates of MBPT i.e. upto 31 March, 2019. The approval accorded shall automatically lapse unless specifically extended by this Authority.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./34/17]